मोनेटरी एंड क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिव्यू

खण्ड XVIII अंक 8 नवंबर 2022

एमसीआईआर

I. मौद्रिक नीति

मौद्रिक नीति समिति की बैठक

रिज़र्व बैंक द्वारा सरकार को भेजे जाने वाली रिपोर्ट पर चर्चा करने एवं उसका प्रारूप तैयार करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45ज़ेडएन के प्रावधानों तथा भारतीय रिज़र्व बैंक मौद्रिक नीति समिति और मौद्रिक नीति प्रक्रिया विनियमन, 2016 के विनियमन 7 के अंतर्गत मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की एक अतिरिक्त बैठक 3 नवंबर 2022 को आयोजित की गई।

बैठक की अध्यक्षता श्री शक्तिकान्त दास, गवर्नर ने की तथा इस बैठक में एमपीसी के सभी सदस्यों- डॉ माइकल देवव्रत पात्र, डॉ राजीव रंजन, डॉ शशांक भिडे, डॉ आशिमा गोयल और प्रो. जयंत आर. वर्मा ने भाग लिया। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

भारतीय रिज़र्व बैंक का केंद्रीय बोर्ड

केंद्र सरकार ने श्री विवेक जोशी, सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार को श्री संजय मल्होत्रा के स्थान पर भारतीय रिज़र्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में नामित किया है। श्री विवेक जोशी का नामांकन 15 नवंबर 2022 से अगले आदेश तक प्रभावी है।

II. विनियमन

इंटरनेट बैंकिंग सुविधा

रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस बात से संतुष्ट होकर कि जनहित में ऐसा करना आवश्यक और उचित है, 1 नवंबर 2022 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के ग्राहकों को लेनदेन सुविधाओं के साथ इंटरनेट बैंकिंग प्रदान करने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों पर लागू पात्रता मानदंड को संशोधित किया। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

गवर्नर ने बैंकों के एमडी और सीईओ के साथ बैठक की

गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक ने 16 नवंबर 2022 को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और कुछ निजी क्षेत्र के बैंकों के एमडी और सीईओ के साथ बैठक की। बैठक में भारतीय रिज़र्व बैंक के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों के साथ श्री एम. के. जैन, उप गवर्नर भी शामिल हुए।

गवर्नर ने अपने परिचयात्मक वक्तव्य में, महामारी की शुरुआत के बाद और वित्तीय बाजार में चल रहे उथल-पुथल के कारण उत्पन्न मुश्किल समय के दौरान आर्थिक संवृद्धि का समर्थन करने में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में बताया। उन्होंने आगे कहा कि चुनौतियों के बावजूद, भारतीय बैंकिंग क्षेत्र आघात सहनीय बना हुआ है और विभिन्न कार्यनिष्पादन मानकों में लगातार सुधार कर रहा है। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ)

रिज़र्व बैंक ने 23 नवंबर 2022 को चलनिधि जोखिम प्रबंधन ढांचे के अंतर्गत एसडीएफ के प्रयोग के संबंध में बैंकों को सूचित किया कि एसडीएफ के अंतर्गत बैंकों द्वारा रिज़र्व बैंक के पास रखी गई एकदिवसीय शेष राशियां चलनिधि कवरेज अनुपात

खंड विषयवस्तु पृष्ठ

i.	मौद्रिक नीति	1
ii.	विनियमन	1
iii.	बैंकों का बैंक	2
iv.	वित्तीय स्थिरता विश्लेषण	2
v.	बाह्य निवेश और परिचालन	2
vi.	विदेशी मुद्रा प्रबंधन	2
vii.	वित्तीय समावेशन और विकास	3
viii.	उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण	3
ix.	बैंक ऋण	3
x..	फिनटेक	3
xi.	भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रकाशन	3
xii.	जारी आंकड़े	4

संपादक की कलम से

मोनेटरी एवं क्रेडिट इंफर्मेशन रिव्यू (एमसीआईआर) के एक और संस्करण में आपका स्वागत है। रिज़र्व बैंक की यह मासिक आवधिक पत्रिका धन और ऋण की दुनिया में रिज़र्व बैंक द्वारा नवंबर 2022 महीने के दौरान किए गए नए विकास और महत्वपूर्ण नीतिगत पहलुओं के साथ जुड़े रहने में आपकी मदद करती है। एमसीआईआर को https://mcir.rbi.org.in पर और साथ ही क्यूआर कोड को स्कैन करके देखा जा सकता है।

संवाद के इस माध्यम से सूचनाएं साझा करने, शिक्षित करने और आप सबसे जुड़े रहने के साथ हमारा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना भी है कि प्रसारित की जा रही सूचनाओं में तथ्यात्मक सटीकता एवं संगति रहे।

हम आपकी प्रतिक्रिया का mcir@rbi.org.in पर स्वागत करते हैं।

योगेश दयाल
संपादक

की गणना के लिए 'स्तर 1 उच्च गुणवत्ता वाली चलनिधि आस्तियां' के रूप में पात्र होगी। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

एनबीएफ़सी के पंजीकरण प्रमाणपत्र

रिज़र्व बैंक ने 10 नवंबर 2022 को दो गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफ़सी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें। इसके अलावा, पाँच एनबीएफ़सी ने रिज़र्व बैंक द्वारा उन्हें प्रदान किए गए पंजीकरण प्रमाणपत्र का अभ्यर्पण किया। रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इन कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

खाता एग्रीगेटर ढांचा

रिज़र्व बैंक ने 23 नवंबर 2022 को खाता एग्रीगेटर (एए) ढांचे के अंतर्गत वित्तीय सेवा प्रदाता (एफ़आईपी) के रूप में माल और सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) को शामिल करने का निर्णय लिया। इस विशिष्ट उद्देश्य तथा माल और सेवा कर विवरणियों के लिए राजस्व विभाग जीएसटीएन का विनियामक होगा। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

सहयोग पत्र

रिज़र्व बैंक ने 30 नवंबर 2022 को वित्तीय सेवाएं एजेंसी, जापान के साथ आपसी सहयोग में सुधार के उद्देश्य से केंद्रीय प्रतिपक्षकारों के क्षेत्र में सहयोग पत्रों का आदान-प्रदान किया। ये पत्र दोनों देशों के संबंधित विधियों और विनियमों के अनुरूप सहयोग बढ़ाने में दोनों देशों के हित की पुष्टि करते हैं। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

III. बैंकों का बैंक

प्रत्यक्ष कर संग्रहण

रिज़र्व बैंक ने 14 नवंबर 2022 को एजेंसी बैंक द्वारा सरकारी कारोबार के परिचालन – एजेंसी कमीशन का भुगतान संबंधी दिनांक 1 अप्रैल 2022 के मास्टर परिपत्र के पैरा 21 को संशोधित करने का निर्णय लिया। संशोधित पैराग्राफ 21 यह दर्शाता है कि एजेंसी बैंकों को एजेंसी कमीशन के लिए अपने दावे निर्धारित प्रारूप में, केंद्रीय सरकार के लेनदेनों के लिए सीएएस नागपुर को और राज्य सरकार के लेनदेनों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत करना अपेक्षित है। तथापि, जीएसटी प्राप्ति लेनदेनों तथा TIN 2.0 व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्यक्ष कर संग्रहण के लेनदेन से संबंधित एजेंसी कमीशन के दावों का निपटान केवल मुंबई कार्यालय द्वारा किया जाएगा और तदनुसार जीएसटी और TIN 2.0 के अंतर्गत प्रत्यक्ष कर का संग्रहण करने वाले प्राधिकृत सभी एजेंसी बैंकों को सूचित किया कि वे संबंधित प्राप्ति लेनदेनों से संबंधित एजेंसी कमीशन के अपने दावे केवल मुंबई कार्यालय में ही प्रस्तुत करें। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

IV. वित्तीय स्थिरता विश्लेषण

वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद

रिज़र्व बैंक ने 15 नवंबर 2022 को वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की उप-समिति की 29वीं बैठक आयोजित की। श्री शक्तिकांत दास, गवर्नर ने बैठक की अध्यक्षता की। उप-समिति ने वैश्विक और घरेलू अर्थव्यवस्था के साथ-साथ वित्तीय प्रणाली के विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रमुख गतिविधियों की समीक्षा की। उप-समिति ने अपने दायरे में आने वाले विभिन्न तकनीकी समूहों की गतिविधियों और विभिन्न राज्यों/ संघ शासित प्रदेशों में राज्य स्तरीय समन्वय समितियों के कामकाज की भी समीक्षा की। रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर श्री महेश कुमार जैन, डॉ. माइकल देवव्रत पात्र और श्री टी. रबी शंकर; तथा कार्यपालक निदेशक डॉ. ओ. पी. मल्ल और श्री सौरव सिन्हा ने बैठक में भाग लिया। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

V. बाह्य निवेश और परिचालन

विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों का प्रबंधन

रिज़र्व बैंक ने 4 नवंबर 2022 को सितंबर 2022 के अंत के संदर्भ में विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों के प्रबंधन संबंधी 39वीं छमाही रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट यह दर्शाती है कि आयात के लिए विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों की पर्याप्तता (भुगतान संतुलन के आधार पर) 11.8 महीने (मार्च 2022 के अंत) से घटकर 10.4 महीने (जून-2022 के अंत) हो गई। इसी अवधि में आरक्षित निधियों की तुलना में अल्पावधि ऋण (मूल परिपक्वता) का अनुपात, 20.0% से बढ़कर 22.0% हो गया। आरक्षित निधियों की तुलना में अस्थिर पूंजी प्रवाह का अनुपात मार्च 2022 के अंत में 66.6% से बढ़कर जून 2022 के अंत में 67.6% हो गया। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

VI. विदेशी मुद्रा प्रबंधन

मॉरीशस को ऋण व्यवस्था

भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने 17 अक्तूबर 2022 को भारत सरकार द्वारा समर्थित 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण व्यवस्था (एलओसी) उपलब्ध कराने हेतु एसबीएम (मॉरीशस) इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (एसबीएमआईडीसीएल) के साथ 7 नवंबर 2022 से प्रभावी करार किया है ताकि उसे मॉरीशस में मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना के चरण-IV के निर्माण का कार्य प्रारंभ करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं में मोचनीय अधिमानी शेयरों के माध्यम से सहभागिता करने हेतु वित्तपोषण प्राप्त हो सके। रिज़र्व बैंक ने 17 नवंबर 2022 को इस उद्देश्य के लिए भारत से पात्र वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात संबंधी निदेश जारी किए। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

VII. वित्तीय समावेशन और विकास

अग्रणी बैंक का कार्यभार सौंपना

नागालैंड सरकार ने नागालैंड राज्य में चार नए जिलों के गठन को अधिसूचित किया है। रिज़र्व बैंक ने 17 नवंबर 2022 को नए जिलों के अग्रणी बैंकों को नामित करने का निर्णय लिया। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

ब्याज सहायता (सबवेंशन) योजना

रिज़र्व बैंक ने 23 नवंबर 2022 को सूचित किया कि भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 और 2023-24 के लिए संशोधन के साथ, किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से प्राप्त कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए अल्पावधि ऋणों हेतु संशोधित ब्याज सहायता योजना को जारी रखने की मंजूरी दे दी है और इसके लिए शर्तें भी जारी कीं है। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

VIII. ग्राहक शिक्षण और संरक्षण

राष्ट्रव्यापी जागरूकता कार्यक्रम

ग्राहक जागरूकता में सुधार और उपभोक्ता हितों की रक्षा के लिए की गई कई पहलों के एक हिस्से के रूप में, रिज़र्व बैंक ने नवंबर 2022 में, अपनी विनियमित संस्थाओं के सहयोग से राष्ट्रव्यापी उपभोक्ता वित्तीय जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों की आबादी को शामिल किया गया ताकि बेहतर जुड़ाव के लिए इसे क्षेत्रीय आधार पर चलाया जा सके और ग्राहक के अधिकारों, ग्राहक संरक्षण और शिकायत निवारण ढांचे के बारे में बताया जा सके। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

IX. बैंक ऋण

बैंक ऋण का क्षेत्र-वार अभिनियोजन

खाद्येतर बैंक ऋण ने एक वर्ष पहले के 6.9% की तुलना में अक्तूबर 2022 में वर्ष-दर-वर्ष (व-द-व) आधार पर 18.3% की वृद्धि दर्ज की। अलग-अलग स्तर पर बैंक ऋण संवृद्धि को मुख्य रूप से 'एनबीएफसी', 'वाणिज्यिक स्थावर-संपदा' और 'व्यापार' क्षेत्रों के प्रति सुधारित ऋण उठाव के कारण सेवा क्षेत्र (22.2%) द्वारा समर्थन प्रदान किया गया; उद्योग क्षेत्र (13.6%) को 'सभी इंजीनियरिंग', 'मूल धातु और धातु उत्पादों', 'पेय पदार्थ और तंबाकू', 'सीमेंट और सीमेंट उत्पादों', 'रसायन और रासायनिक उत्पादों', 'निर्माण', 'खाद्य प्रसंस्करण', 'कांच और कांच के बने पदार्थ', 'अवसंरचना', 'चमड़ा और चमड़े के उत्पादों', 'खनन और उत्खनन', 'पेट्रोलियम, कोयला उत्पादों और परमाणु इंधनों', 'वाहन, वाहन के पुर्जों और परिवहन उपकरण' एवं 'लकड़ी और लकड़ी के उत्पादों तथा कृषि क्षेत्र (13.6%) द्वारा समर्थन प्रदान किया गया। माह के दौरान व्यक्तिगत ऋण में 20.2% की वृद्धि हुई। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की उधार और जमा दरें

भारतीय रिज़र्व बैंक ने नवंबर 2022 माह के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) की उधार और जमा दरों संबंधी आंकड़े जारी किए। आंकड़ों से पता चलता हैं कि एससीबी की निधि आधारित उधार दर की एक-वर्ष माध्यिका सीमांत लागत अक्तूबर 2022 में 7.90 प्रतिशत से बढ़कर नवंबर 2022 में 8.05 प्रतिशत हो गई।

इसके अलावा, एससीबी के नए रुपया ऋणों पर भारित औसत उधार दर (डब्ल्यूएएलआर) सितंबर 2022 में 8.59 प्रतिशत से 9 आधार अंक (बीपीएस) बढ़कर अक्तूबर 2022 में 8.68 प्रतिशत हो गई। एससीबी के बकाया रुपया ऋणों पर डब्लूएएलआर सितंबर 2022 में 9.22 प्रतिशत से 13 बीपीएस बढ़कर अक्तूबर 2022 में 9.35 प्रतिशत हो गया। दूसरी ओर, एससीबी की बकाया रुपया सावधि जमा पर भारित औसत घरेलू सावधि जमा दर सितंबर 2022 में 5.39 प्रतिशत से 10 बीपीएस बढ़कर अक्तूबर 2022 में 5.49 प्रतिशत हो गई। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

X. फिनटेक

केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 1 दिसंबर 2022 को रिटेल डिजिटल रुपया (ई₹-आर) के पहले प्रायोगिक परिचालन शुरू करने की घोषणा 29 नवंबर 2022 को की। इस प्रायोगिक परिचालन में चुनिंदा स्थानों के सीमित उपयोगकर्ता समूह (सीयूजी) को सम्मिलित किया जाएगा, जिसमें उक्त परिचालन में भाग लेने वाले ग्राहक और व्यापारी शामिल होंगे। ई₹-आर एक डिजिटल टोकन के रूप में होगा, जिसे वैध मुद्रा की मान्यता प्राप्त होगी। यह मध्यवर्ती संस्थाओं, अर्थात्, बैंकों के माध्यम से वितरित किया जाएगा। यह लेनदेन पर्सन टू पर्सन (पी2पी) और पर्सन टू मर्चेंट (पी2एम) दोनों तरह से किए जा सकते हैं। व्यापारी के स्थानों पर प्रदर्शित क्यूआर कोड का उपयोग करके व्यापारियों को भुगतान किया जा सकता है। यह ई₹-आर, भौतिक नकदी की तरह ही विश्वास, सुरक्षा और अंतिम निपटान जैसी सुविधाएं प्रदान करेगा।

इस प्रायोगिक परिचालन में चरणबद्ध सहभागियों के लिए आठ बैंकों की पहचान की गई है। पहला चरण देश भर के चार शहरों में चार बैंकों, अर्थात्, भारतीय स्टेट बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, यस बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ शुरू होगा। चार अन्य बैंक, अर्थात्, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक बाद में इस प्रायोगिक परिचालन में शामिल होंगे। इस प्रायोगिक परिचालन के शुरुआत में चार शहरों, अर्थात्, मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर को शामिल किया जाएगा और बाद में इसे अहमदाबाद, गंगटोक, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, कोच्चि, लखनऊ, पटना और शिमला तक बढ़ाया जाएगा। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

XI. भारतीय रिज़र्व बैंक का प्रकाशन

नगरपालिका वित्त संबंधी रिपोर्ट

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 10 नवंबर 2022 को नगरपालिका वित्त संबंधी रिपोर्ट का अपना पहला संस्करण जारी किया। सभी राज्यों की 201 नगरपालिकाओं (एमसी) के बजटीय

आंकड़ों का संकलन और विश्लेषण करते हुए रिपोर्ट, अपने विषय के रूप में 'नगरपालिकाओं के लिए वित्तपोषण के वैकल्पिक स्रोत' का परीक्षण करता है।

मुख्य बिंदु:

ए) भारत में शहरीकरण की तीव्र वृद्धि के अनुरूप शहरी अवसंरचना में वृद्धि नहीं हुई है।

i) भारत में नगरपालिका बजट का आकार बहुत कम है तथा राजस्व मुख्यतया संपत्ति कर संग्रह और सरकार के ऊपरी स्तरों से करों के अंतरण और अनुदानों से प्रभावित रहता है, जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय स्वायत्तता की कमी देखी जाती है।

ii) नगरपालिकाओं का पूंजीगत व्यय न्यूनतम है, जबकि स्थापना व्यय, प्रशासनिक लागत और ब्याज तथा वित्त शुल्क बढ़ रहा है।

iii) नगरपालिका बॉण्डों के लिए एक सुविकसित बाजार की अनुपस्थिति में, अपने संसाधन अंतराल को पूरा करने हेतु नगरपालिकाएँ, ज्यादातर बैंकों और वित्तीय संस्थानों, केंद्र/राज्य सरकारों से उधार पर निर्भर रहते हैं।

बी) नगरपालिकाओं को अपने संसाधनों को बढ़ाने के लिए उचित निगरानी तथा प्रलेखन के साथ सुदृढ़ और पारदर्शी लेखांकन प्रथाओं को अपनाने और विभिन्न नवोन्मेशी बॉण्ड और भूमि आधारित वित्तपोषण तंत्र का पता लगाने की आवश्यकता है। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन– नवंबर 2022

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 18 नवंबर 2022 को अपने मासिक बुलेटिन का नवंबर 2022 का अंक जारी किया। बुलेटिन में आठ भाषण, पाँच आलेख और वर्तमान सांख्यिकी शामिल हैं।

पाँच आलेख हैं: I. अर्थव्यवस्था की स्थिति; II. जब किसी समाचार के मायने उसके शब्दों से कहीं ज्यादा हैं: भारतीय अर्थव्यवस्था से साक्ष्य; III. हरित डेटा केंद्र: सतत डिजिटलीकरण का मार्ग; IV. आर्थिक संकेतकों के रूप में भुगतान प्रवाह: हाइब्रिड मशीन लर्निंग फ्रेमवर्क का उपयोग करते हुए तात्कालिक पूर्वानुमान; और V. भारत में स्थिर निवेश के लिए वित्तीय स्थितियों का संचरण: एक तथ्यात्मक अन्वेषण।

I. अर्थव्यवस्था की स्थिति

वैश्विक अर्थव्यवस्था के परिदृश्य में गिरावट का जोखिम बना हुआ है। भारत में, अर्थव्यवस्था में आपूर्ति प्रतिसाद मजबूत हो रही हैं। मुद्रास्फीति में कमी होने के संकेत प्राप्त हो रहे हैं। शहरी मांग मजबूत प्रतीत हो रही है। ग्रामीण मांग में गति आ रही है।

II. जब किसी समाचार के मायने उसके शब्दों से कहीं ज्यादा हैं: भारतीय अर्थव्यवस्था से साक्ष्य

इस आलेख में समष्टिआर्थिक चर की एक श्रृंखला के संबंध में रुख सूचकांकों का निर्माण किया गया है और भारतीय संदर्भ में आर्थिक विश्लेषण के लिए उनकी उपयोगिता को परखा गया है। लेख में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि कोविड-19 महामारी ने रुख को दबा दिया था, हालांकि, आर्थिक गतिविधियों के धीरे-धीरे फिर से शुरू होने और सामान्य स्थिति की ओर लौटने से रुख में सुधार हुआ।

III. हरित डेटा केंद्र: सतत डिजिटलीकरण का मार्ग

इस आलेख में बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए डेटा केंद्रों के महत्त्व, पर्यावरण पर उनके प्रभाव और हरित डेटा केंद्रों के लाभ के बारे में चर्चा की गई है। इसके अलावा, लेख में ऐसे सुझाव दिए गए हैं जो बैंकों और वित्तीय संस्थानों को अपने डेटा केंद्रों को हरित बनाने में मदद कर सकते हैं।

IV. आर्थिक संकेतकों के रूप में भुगतान प्रवाह: हाइब्रिड मशीन लर्निंग फ्रेमवर्क का उपयोग करते हुए तात्कालिक पूर्वानुमान

कुशल भुगतान और निपटान प्रणाली के संबंध में यह अध्ययन, योजित सकल मूल्य में संवृद्धि संबंधी पूर्वानुमान के लिए भुगतान डेटा के उपयोग का परीक्षण करता है।

V. भारत में स्थिर निवेश के लिए वित्तीय स्थितियों का संचरण: एक प्रायोगिक अन्वेषण

इस आलेख में, वित्तीय स्थिति सूचकांकों के निर्माण के लिए गतिक कारक मॉडल और सदिश (वेक्टर) स्वत: प्रतिगमन पद्धतियों का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा, भारत में निवेश संवृद्धि पर वित्तीय स्थितियों के प्रभाव, और संबंधों में विषमता का प्रायोगिक अन्वेषण किया गया है ताकि निवेश के प्रति जोखिमों का पता लगाया जा सके। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

भारतीय राज्यों पर सांख्यिकी हैंडबुक

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 19 नवंबर 2022 को "भारतीय राज्यों पर सांख्यिकी हैंडबुक 2021-22" शीर्षक से अपने सांख्यिकीय प्रकाशन के सातवें संस्करण को जारी किया। इस प्रकाशन के माध्यम से, भारतीय रिज़र्व बैंक भारत की क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था पर व्यापक आंकड़ों का प्रसार करता है। हैंडबुक के वर्तमान संस्करण में, दो नए खंड अर्थात्, स्वास्थ्य और पर्यावरण को प्रस्तुत किया गया है। मौजूदा आंकड़ों की श्रृंखला के अद्यतन के अलावा, 9 नई तालिकाएँ शामिल की गई हैं। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

पुस्तक लेखन के लिए पुरस्कार योजना

आर्थिक/बैंकिंग/वित्तीय विषयों पर मूल रूप से हिंदी में किताबें लिखने के लिए पुरस्कार योजना के अंतर्गत रिज़र्व बैंक भारतीय विश्वविद्यालयों के कार्यरत/ सेवानिवृत्त प्रोफेसरों को ₹1.25 लाख के तीन पुरस्कार प्रदान करता है। रिज़र्व बैंक ने 15 नवंबर 2022 को उक्त योजना के अंतर्गत नामांकन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2023 निर्दिष्ट की। योजना के विवरण के लिए कृपया यहां क्लिक करें।

X. जारी आंकड़े

नवंबर 2022 के दौरान रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए महत्वपूर्ण आंकड़े निम्नानुसार हैं:

क्रम सं.	शीर्षक
1.	अंतरराष्ट्रीय सेवा व्यापार: सितंबर 2022
2.	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की जमा और ऋण पर सांख्यिकी: सितंबर 2022
3.	ईसीबी/एफ़सीसीबी/आरडीबी: अक्तूबर 2022
4.	समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश: अक्तूबर 2022
5.	भारत की अदृश्य मदों पर आंकड़े: अप्रैल-जून 2022-23
6.	बैंक ऋण का क्षेत्र-वार अभिनियोजन: अक्तूबर 2022
7.	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की उधार और जमा दरें: नवंबर 2022

योगेश दयाल द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक, संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, मुंबई - 400 001 के लिए संपादित और प्रकाशित। मोनेटरी एंड क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रीव्यू https://mcir.rbi.org.in पर उपलब्ध है।